. 1 .7010

श्रम विभाग

म्रादेश

्दिताक 22 मई, 1985 .

हैं और ति/गृहगांवा/31-85/22111 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि मैं विज्ञों लिंव दिल्ली रोड़, मुंडमांवा के समिक सी कहेन्द्र कुमार तथा उसके प्रयन्तकों के भव्य इसमें इसके बाब लिखित मामले में कोई सौद्रोणिक दिवाद है;

भीर चूंचि इरियाचा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना बोक्रनीय समझते हैं ; 🎺

श्वामिष्, सब, सीसोगिक विवाद सिंधिनियम, 1947, की खारा 10 की उपधारा (1) के संबद (ग) हारा प्रधान की वर्द गरितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाना के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मिश्चपूना सं. 5416—5—44/68/15254, दिनांक 20 पून; 1868, के साम पढ़ते हुये मिश्चपूनना सं. 11495—जी—अम |88—अस/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उपत स्विधिक्य की सारा 7 के संबोद्ध गरित जम न्यायालय, करीदाबाद, को विवादप्रका या उससे सुखंगत या उससे सुसंगत या उससे व्याविधिक के सिवे निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रकाशकों तथा जिसका के बीच या तो विवादप्रका या उससे सुसंगत या उससे स्वाविध्य वामना है:—

क्या की महेन्द्र कुमार की सेवाबों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हुकदार है ?

सं भो. वि./गृहगांवा/290-85/22118.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं टर्टिंगर लाक लिंव क्लाट नं 3 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम गुड़गांवा रोड़ गुड़गांवा, के अभिक श्री एम.सी: सकारिय तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामसे में नीई भोदोगिक विवाद है;

भीर चूंकि इरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णम हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते हैं;

इसलिए, यथ, धींचोगिक विंवाद प्रिवित्यम, 1947 की धारा 10 की उपदारा (1) के खण्ड (ग) होरा प्रदान की गई सिल्त्यों का प्रयोग करते हुए प्रिवित्यम के राज्यपाल इसके हारा सरकारी प्रिवित्यमा सं. 5415-3-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए प्रविद्युचना सं. 11495-जी-ध्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, हारा उक्त सिलियम की घारा 7 के प्रधीन गठित श्रम स्थायालय, फरीदाबाद, को विवाहमस्त था उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा बाबसा न्यायालय के लिए निर्विष्ट करते हैं, जी कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाहमस्त या उससे सुसंगत मामला है:—

क्या औ एम. सी. सकारिय की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सी वृद्ध किस राहत का हकदार है ?

चै॰ बो. वि, गृहगांवा /34-85/22154.—चूंकि इरिवासा के राज्यवास की दाव है कि मैं० कुन्दना सन्स इण्डिया प्रा॰ लि ; खान्डसा रोड़ गृहगांवा के समिस्न श्री कुंबर सिंह तथा एसके प्रवासकों के सन्ध इसमें इसके बाद शिक्षित मामले में कोई सीसोविक विवाद है:

कीर चूंकि हरियाणा के राज्यवान दिवाद को न्यायनिर्वय होतू निर्दिश्त करना वांक्रनीक समझहे हैं ; 🚧 🕟

वर्षावर, जब, श्रीकोष्ट्रिक विवाद महिनियम, 1947, की बारा 10 की क्षवकारा (1) के क्षवक (ग) हारा महाव की वर्ष करितवों का अविश्व कर्षों हुए, इरियाण के राज्यपान इसके हारा सरकारी महिनुक्ता है. 5415-3 अम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साब पहते हुए अधिसूचना 'सं॰ 11495-जी-वर्ष-38-अम/57/11245,' दिनांक' '7 'फरवरी, 1958' हारा उक्त किशियक की वारा 7' के मधीन गढ़ित अम[ि]न्यायालय, फरीदाबाद को विवादकर्त था उससे सुसंगत या उससे सुकंगत या

विशा औं कुंबर सिंह की क्षेत्राओं का समापन त्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं; तो वह किस राहत का इकतार है ?

ें के में भी कि | सीनी फेत | 40-85 | 22160 --- चूकि हरियाण के राज्यपाल की राम है कि मैं अभित इन्जीनियर्ज 20-बी मी ल शेंई सीनीपत, के अभिक बी राम चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में बाई सीचीणक विवाद है।

भीर चूंकि हरियाणा. के राज्यपाल विवाद को ग्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, श्रीकोणिक विवाद श्रिधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नव स्वर, 1970 के साथ गठित सरकारी श्रिधिसूचना सं. 3864-ए-एस-श्रो. (ई)-श्रम/70/1348; दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादशस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

मया श्री राम चन्द्र की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. मो.बि./यमुनानगर/103-85/22166.---चृष्णि द्वरियाणा के राज्यपास की राय है कि मैं • (1) सचिव हरियाण राज्य विजलो बोडं चण्डीगढ़ (2) कार्यकारी ग्रभियन्त होडल प्रोजैक्ट एच.एस. ई.बी. बुडकलान के श्रमिक भी मुनसी रामा तथा उसके प्रकारतों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामने में कोई घोडोगिक विवाद है;

भीर चुंकि हरियाण के राश्यपाल विचाद को ध्यायनिर्गंग हेतु निर्दिष्ट सरमा बाक्तिय समझते हैं।

इस लिए, पन, पीदोगिक निवाद प्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के सम्ब (ग) द्वारा प्रदान की गई सक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा धरकारी प्रधिसूचना हैं 3 (44)84-3%म, दिनांक 18 प्रप्रेल, 1984 द्वारा उक्त प्रिवित्यम की धारा 7 के प्रधीन गठित अमन्यायालय, अन्त्राला, को जिवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निक्थि करते हैं, जो कि उनत प्रबन्धकों चया श्रमिक के बोच या तो निवादग्रस्त मामला है या निवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

पया श्री मुमसी राम की सेवाघों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो बह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 23 मई, 1985

एं भो विव /यमुना / 45-85 / 22221. — चूं कि हिर्याणा के राज्यपाल की राये है कि मै. स्वास्तिका मैटल वकेंस, जगादरी, के धिमक ब्री बलदेव राम सथा उसके प्रवासकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई घोडोगिक दिवाद है;

भीर चूंकि तुरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना वाछनीय समझते हैं;

इसलिए, घर, भौबोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मिनतयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिभूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्वाला, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे खिखा मामला न्यायिनगंय केलिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या हो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से स्वंधित मामला है :---

नया श्री वलदेव राम की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है। यदि नहीं, तो यह किस राह्त का हुछक्षर है ?

सं॰ मो॰ वि॰ /यमुना / 1-85 / 22227. -- चूंकि स्रियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़. (2) जनरल मैंनेजर हरियाणा, राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सुरेश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित सामने में कोई भी बोगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसिन्ए, प्रब, भोदोपिक विवाद मधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रवान की गई शक्तियों की प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा संरकारी श्रधिसूचना सं 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 श्रशैल, 1984 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला, को विवादप्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादप्रस्त श्रमला है या विवाद से सुसंगत प्रथम संबंधित मामला है:---

क्या थी सुरेश चन्द की सेवाओं का समाधान न्यायोजित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?